International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 08-02-2024, Accepted: 03-03-2024, Published: 26-03-2024
Volume 10, Issue 2, 2024, Page No. 35-39

भारत की दक्षिण एशिया नीतिः 2014–2023

डॉ. करुणा कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

सारांश

विश्व की 3.5 प्रतिशत भूमि और लगभग एक–चौथाई जनसंख्या के साथ दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय विकास मंच पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके देशों की भौगोलिक समीपता और सामाजिक–सांस्कृतिक साम्य के बावजूद इनमें बहुत ही कम समन्वय है। ये देश विश्व व्यापार की तुलना में मात्र 5 प्रतिशत का व्यापार अपने निकट देशों के साथ करते हैं। पूरे क्षेत्र के वैश्विक निवेश को देखें, तो उसका केवल एक प्रतिशत निवेश, ये आसपास के देशों में करते हैं। वैश्विक औसत की तुलना में दक्षिण एशियाई देशों का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मात्र 9.64 प्रतिशत है। विश्व की 30 प्रतिशत गरीबी इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र के लिए अनेक आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ है।

इस क्षेत्र के देश आर्थिक विकास की समान चुनातियों का सामना करते हैं। इसके बावजूद इनके बीच सहयोग बहुत कम है। इस मामले में बिम्सटेक और बीबीआईएन ही दो ऐसे उपक्रम हैं, जिन्हें देशों को आर्थिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे के नजदीक लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इन देशों में असमानता, गरीबी, कमजोर प्रशासन और ढांचों की कमी से जुड़ी समान समस्याएं हैं, जो 2030 के धारणीय विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहयोग, समन्वय और समानता की मांग करती है। अधिकतर दक्षिण एशियाई देशों ने गरीबी को कम करने में अच्छी प्रगति की है, परन्तु उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा, भुखमरी, लैंगिक समानता, शिक्षा, रोजगार, नगरों के विकास आदि क्षेत्रों में वे अभी भी अनेक पहलुओं पर पीछे हैं। ये देश जलवायु परिवर्तन और उससे जन्मी प्राकृतिक आपदाओं के निशाने पर भी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रारंभ में ही सरकार ने 'पड़ोसी पहले' की अपनी नीति का परिचय देना शुरू कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2014 में जहाँ सार्क देशों के प्रमुखों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था, वहीं इस बार बंगाल की खाड़ी से जुड़े बिम्सटेक समूह देश के प्रमुखों को बुलाया गया। बिम्सटेक (BIMSTEC) यानि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाइलैण्ड। इस समूह में चार देश ऐसे हैं, जो सार्क के भी सदस्य हैं। सरकार की इस प्रारंभिक नीति का अर्थ यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारत ने सार्क के विकल्प के रूप में बिम्सटेक को चुन लिया है। भारत के लिए सार्क देशों का अलग महत्व है, और इसे देखा–समझा जाना भी आवश्यक है। भारत सरकार की दक्षिण एशिया नीति वर्ष 2014 के बाद परिवर्तित हुई है।

मूलशब्दः दक्षिण एशिया, विदेश नीति, भू–राजनीतिक रणनीति, बिम्सटेक, सार्क, मोदी सरकार

किसी भी देश की सफल विदेश नीति की कसौटी, उसके पड़ोसी देशों से संबंध होते हैं। भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए यह और भी मायने रखते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री के 2014 में शपथ ग्रहण के साथ ही पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति की शुरूआत हो गई थी। तब से लेकर आज तक भारत सरकार लगातार इस पर अमल करती आ रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्ष के अंत तक प्रधानमंत्री का नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है।

पड़ोसी देशों के प्रति सौहार्दपूर्ण नीति को बनाए रखने में चीन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। चीन की वन बेल्ट, वन रोड़ नीति का कई दक्षिण एशियाई देश विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे हिन्द महासागर में उसकी जगह बन जाएगी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में चीन अपने लिए कुछ मित्र तैयार करना चाह रहा है। इस नीति के तहत उसने नेपाल को अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं बदलने के लिए किसी प्रकार से प्रभावित कर लिया है। इसका साक्ष्य इस बात से मिलता है कि नेपाल ने अगस्त में सम्पन्न बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन) सम्मेलन के बाद, इन देशों के पूना में होने वाले सैन्य अभ्यास के लिए अपने दल को नहीं भेजा (वेग्नर 2020, पृष्ठ संख्या–22)।

पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की भारत की विदेश नीति के साढ़े चार वर्षों के दौर में पाकिस्तान एक ऐसा देश रहा, जिसने भारत की दोस्ती के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया है। इस मामले में सार्क संगठन भी अप्रभावी सिद्ध हुआ है। अतः पाकिस्तान को छोड़कर, भारत ने अन्य सभी पड़ोसी देशों को अपनी आर्थिक प्रगति का भागीदार बनाते हुए, उनके लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने; संपर्क साधनों का जाल बिछाने एवं बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराने के अथक प्रयास किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों की नियमित यात्राएं की हैं, और इन देशों में प्रमुखों की आवभगत भी की है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

प्रत्येक देश को अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चुनने की संप्रभुता होती है। चीन के आर्थिक कौशल और विकास की रफ्तार ने अनके दक्षिण एशियाई देशों को उसकी ओर आकर्षित किया है। इसी के चलते 2014 में श्रीलंका ने चीनी पनडुब्बियों का स्वागत किया था। अब नेपाल भी चीन की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। मालदीव ने भी चीन के दोस्ताना रवैये का स्वागत किया है। चीने के साथ हुआ डोकलाम विवाद भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। चीन ने चाल चलते हुए भूटान के माध्यम से भारत को संदेश देना चाहा था। परन्तु भूटान ने चीन की प्रभुता के सामने घुटने नहीं टेके। इसी प्रकार बांग्लादेश ने भी चीन के साथ संबंधों में चतुराई दिखाते हुए उससे दूरी बनाए रखी। म्यांमार ने चीन की बेल्ट रोड़ नीति का विरोध किया है।

श्रीलंका ने भी अपनी विदेश नीति को अपेक्षाकृत संतुलित कर लिया है। लेकिन चीन के ऋण से दबे होने के कारण उस पर अभी भी दबाव है। अफगानिस्तान तो अतिवादियों से दूर ही रहना चाहता है। मालदीव से संबंध और बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ इतिहास और जड़ों की समानता ही भारत का स्थान बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं

है। भारत को राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर ऐसे समाधान और विकल्प ढूंढने होंगे, जो इन देशों में उसकी सफलता को बनाए रख सके (भारतीय वैश्विक संबंध परिषद 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

भारत और दक्षिण एशियाई देश : आपसी सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा

वर्ष 2014 में, नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। इस कदम ने उस मूल्य को उजागर किया जो भारत अपने पड़ोसियों को देता है। दरअसल, दक्षिण एशियाई देशों पर मोदी सरकार की नीति कनेक्टिविटी में सुधार, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों पर निर्माण और विकासात्मक और मानवीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। भारत की अपने पड़ोसियों तक बढ़ती पहुंच को क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य उपस्थिति के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता का किसी भी देश की विदेश नीति से गहरा संबंध है (गांगुली 2015, पृष्ठ संख्या–1)।

किसी भी सरकार के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को प्रभावी ढंग से और निर्बाध रूप से बढ़ावा देने और वैश्विक मैट्रिक्स में अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए तत्काल पड़ोस या क्षेत्र में स्थिरता महत्वपूर्ण है। जैसा कि भारतीय विदेश नीति विश्लेषक सी राजा मोहन ने ठीक ही कहा है, ''अपने पड़ोस में प्रधानता कायम किए बिना, कोई भी राष्ट्र वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय शक्ति नहीं बन सकता है।'' मोदी सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने के महत्व को अच्छी तरह से समझ गई है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से, मोदी सरकार ने भारतीय विदेश नीति के अभिन्न अंग के रूप में ''पड़ोसी पहले'' नीति पर जोर दिया है। यह नीति अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण और सहक्रियात्मक संबंध बनाने का प्रयास करती है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

हालाँकि, निरंतर स्थिरता लंबे समय से दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए चिंता का कारण रही है। दक्षिण एशिया में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तरों पर लगातार उथल–पुथल ने भारत के पड़ोसी देशों और पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लगातार परेशान किया है। आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की मौजूदा स्थिति नाजुक है। मौजूदा समस्या में उलझे पड़ोस के साथ क्षेत्र में स्थिरता को लेकर चिंताओं को देखते हुए, संकट प्रबंधन में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए चीन की बढ़ती उपस्थिति के साथ स्थिरता के प्रश्न के लिए भारत को अपने पड़ोसी देशों में अपनी उदारता और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करके अपनी सद्भावना को मजबूत करने के लिए एक बेहतर प्रबंधन रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है, जो कि अपेक्षाकृत छोटे हैं। भौगोलिक आकार और आर्थिक ताकत का।

पड़ोस प्रथम नीति

भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को वसुधैव कुटुंबकम (दुनिया को एक परिवार के रूप में) बनाने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। आपसी सम्मान और समान साझेदारी पर आधारित वैक्सीन कूटनीति और विकास सहायता भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को आगे बढ़ाने के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वैक्सीन कूटनीति को वैश्विक महामारी के लिए एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर एक जिम्मेदार नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा गया है (भारतीय वैश्विक संबंध परिषद 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

उल्लेखनीय है कि भारतीय कूटनीति, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान, के परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर जरूरतमंद देशों और उनके लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले आशा के अग्रदूत के रूप में भारत को विश्व मंच पर मान्यता मिली। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत ने अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी (वैक्सीन मैत्री) के जरिए दुनिया के कई देशों और पड़ोसी देशों को कोविड–19 महामारी के दौरान मदद पहुंचाई। इसके अलावा, और इसके बावजूद कि भारत बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था, खासकर दूसरी लहर के दौरान, भारत ने महामारी के सबसे बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और साथ ही, अन्य देशों को चुनौती से निपटने में मदद की (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या– 1)।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैक्सीन मैत्री के प्राथमिक लाभार्थी बांग्लादेश हैं (वाणिज्यिक और अनुदान सहायता के रूप में कुल आपूर्ति में प्छत 22.5928 मिलियन, इसके बाद नेपाल (INR 9.499 मिलियन आपूर्ति); श्रीलंका (INR 1.2640 मिलियन); अफगानिस्तान (INR 1.4680 मिलियन); भूटान (INR 0.55 मिलियन) और मालदीव (INR 0.312 मिलियन)। भारत ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) फंड में 10 मिलियन डॉलर देने का भी वादा किया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए, भारत अपनी विकास सहायता पहल के माध्यम से अफगानिस्तान और श्रीलंका को उनकी असंख्य चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में गेहूं और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री और कोविड–19 टीकों की आपूर्ति की है। 2022–23 के अपने बजट में, भारत ने अफगानिस्तान को विकास सहायता के रूप में 2,000 मिलियन रुपये की राशि आवंटित की है (भारतीय वैश्विक संबंध परिषद 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

भारत सरकार ने अपने 2022–23 के बजट में भारत के पड़ोस और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को विकास सहायता के लिए 62,920 मिलियन रुपये आवंटित किए हैं। विकास सहायता के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने भूटान को 22,660 मिलियन रुपए, नेपाल को 7,500 मिलियन रुपए, म्यांमार को 6,000 मिलियन रुपए, मालदीव को 3,600 मिलियन रुपए, बांग्लादेश को 3,000 मिलियन रुपए और बांग्लादेश को 2,000 मिलियन रुपए आवंटित किए। क्रमशः श्रीलंका को मिलियन। श्रीलंका में चल रहे गंभीर आर्थिक संकट को देखते हुए भारत श्रीलंका को 1 अरब डॉलर की ऋण सुविधा देने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा, भारत ने बिजली संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को ईंधन भेजा। इसके अलावा, भारत ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति में भी श्रीलंका की मदद की (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देकर दक्षिण एशियाई देशों को भारत की आवश्यक मदद, विशेष रूप से संकट के समय में श्रीलंका और अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करना, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के महत्व का प्रमाण है। भविष्य में नेबरहुड फर्स्ट नीति पर जोर देने के और भी कारण हैंरू पहला, पड़ोसी देशों के साथ निरंतर जुड़ाव से क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में मदद मिलेगी, जो क्षेत्र में स्थिरता, विश्वास और प्रगति स्थापित करने में लगातार बाधा रही है।

स्थिरता भारत को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में वृद्धि और विकास को

सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाएगी। दूसरा, आवश्यक सहायता प्रदान करके, भारत इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और चीन के मुकाबले आर्थिक और रणनीतिक दोनों गहराई हासिल कर सकता है। इसलिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर जुड़ाव की अधिक आवश्यकता है। तीसरा, निरंतर सौहार्द और स्थिरता के लिए लोगों से लोगों के बीच संबंधों और गहरी सांस्कृतिक समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को शीघ्र पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हाल के घटनाक्रम–श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में– उस भौगोलिक अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं जो भारत को उपमहाद्वीप में अपने पड़ोसियों से जोड़ती है। साथ में, उन्हें क्षेत्र के नेताओं को याद दिलाना चाहिए कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण गहराते क्षेत्रीय और वैश्विक संकटों के बीच भूगोल के तर्क के साथ काम करना एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। चूंकि तेल और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें पूरे क्षेत्र में मुद्रास्फीति और लोकप्रिय अशांति को बढ़ाती हैं, इसलिए अधिक गहन क्षेत्रीय सहयोग नए खतरों के प्रबंधन के लिए एक उपकरण है। पिछले कुछ हफ्तों में उस दिशा में कुछ सकारात्मक रुझान के साथ–साथ भूगोल के तर्क को खारिज करने वाली नकारात्मक नीतियों को भी देखा गया है।

उपमहाद्वीप में इस सकारात्मक परंपरा का एक खतरनाक दूसरा पहलू भी है। 1980 के दशक की शुरुआत में श्रीलंकाई तमिल विद्रोहियों को प्रशिक्षित करने और हथियार देने के फैसले के लिए भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उम्मीद है कि यह भारत की उभरती पड़ोस नीति में नियम के बजाय एक अपवाद है। हालाँकि श्रीलंका के आंतरिक मामलों में भारत का दखल तमिल मांगों को पूरा करने में सफल नहीं हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से इसने दिल्ली और सिंहली राष्ट्रवादियों के बीच गहरे अविश्वास को बढ़ावा दिया (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या–1)। परिणामस्वरूप, कोलंबो में भौगोलिक अनिवार्यता नष्ट हो गई।

लेकिन श्रीलंका में मौजूदा संकट ने द्वीप राष्ट्र में आंतरिक जातीय विभाजन को पार करने और कोलंबो और दिल्ली के बीच राजनीतिक विश्वास के पुनर्निर्माण की उम्मीदें जगाई हैं। निश्चित रूप से, संकटों से प्रेरित सकारात्मक भावनाएँ हमेशा टिकी नहीं रहती हैं। लेकिन इस अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौरान कोलंबो के लिए दिल्ली के अटूट समर्थन – भौतिक और वित्तीय दोनों – ने श्रीलंका में बहुत सद्भावना पैदा की है। यह कोलंबो के साथ दिल्ली के संबंधों को नया रूप देने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

यदि श्रीलंका के साथ भारत के संबंध राजनीतिक भूगोल के निरंतर महत्व को रेखांकित करते हैं, तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी की यात्रा, उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय संबंधों को नया आकार देने में सांस्कृतिक भूगोल की अपार संभावनाओं को उजागर करती है। भारत–नेपाल सीमा के पार विभिन्न तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले ''बौद्ध सर्किट'' का विचार लंबे समय से चल रहा है। वैश्विक बौद्ध आबादी के विशाल आकार – अनुमानित 500 मिलियन से अधिक – और ऐतिहासिक स्थलों में व्यापक अंतरराष्ट्रीय रुचि को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात है कि बौद्ध सर्किट विकसित करने में दिल्ली और काठमांडू को एक साथ आने में कितना समय लगा (भारतीय वैश्विक संबंध परिषद 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

चीन ने लुंबिनी के पास एक नया हवाई अड्डा बनाया है और मोदी इससे बच रहे हैं, जो दिल्ली, काठमांडू और बीजिंग के बीच अशांत त्रिकोणीय गतिशीलता की ओर इशारा करता है। इससे भी अधिक परिणामी नेपाल के राजनीतिक वर्ग के एक बड़े वर्ग की गहरी बेचैनी है – विशेष रूप से कम्युनिस्ट जो पिछले दो दशकों में काठमांडू पर हावी रहे हैं – भारत के संबंधों के साथ। नेपाल कांग्रेस की कमान में वापसी और भारत के साथ संबंधों को गहरा करने की इसकी तत्परता ने काठमांडू के साथ दिल्ली के संबंधों के पुनर्मूल्यांकन का द्वार भी खोल दिया है। साझा सांस्कृतिक भूगोल को पुनर्जीवित करने में अनिवार्य रूप से आर्थिक भूगोल का बेहतर प्रबंधन शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय पक्ष में बुनियादी ढांचे के विकास पर कदम बढ़ाया है और पूर्वी उपमहाद्वीप में सीमा पार परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी में तेजी लायी है (पटनायक 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

दक्षिण एशिया में धर्म और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पूरे क्षेत्र में सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन तक सीमा पार पहुंच में सुधार करने से न केवल सभी दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटक राजस्व में सुधार हो सकता है, बल्कि राष्ट्रों के बीच अशांत राजनीतिक संबंधों पर भी शांत प्रभाव पड़ सकता है।

अपने जमे हुए द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों के बावजूद, दिल्ली और इस्लामाबाद 2019 के अंत में अपनी सैन्यीकृत पंजाब सीमा के पार करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर सहमत हुए थे। यह गलियारा सिख तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान के करतारपुर स्थित मंदिर की यात्रा को आसान बनाता है, जहां गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। उपमहाद्वीप के पवित्र भौगोलिक क्षेत्रों को फिर से जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है – जिसमें रामायण मार्ग और सूफी तीर्थस्थल भी शामिल हैं।

जबकि क्षेत्र के कुछ हिस्से अपनी नीतियों को भौगोलिक अनिवार्यता के साथ जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान एक अपवाद प्रतीत होगा। कुछ लोग कहेंगे, इस्लामाबाद की नीतियां जानबूझकर भौगोलिक विरोधी हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में अपने उच्चायोग में एक ''व्यापार अधिकारी'' की नियमित नियुक्ति पर पाकिस्तान में हालिया विवाद पर विचार करें।

मीडिया की आलोचना का सामना करते हुए, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार को स्पष्ट करना पड़ा कि वह भारत के साथ व्यापार संबंधों में सुधार करने की योजना नहीं बना रही है। अपने व्यापक आर्थिक संकट और भारी मुद्रास्फीति की गहराई को देखते हुए, किसी ने सोचा होगा कि पाकिस्तान अपने आर्थिक हित में भारत के साथ व्यापार संबंधों का विस्तार करना चाहेगा। लेकिन पाकिस्तान की राजनीति भूगोल के तर्क के विपरीत है।

पिछले साल फरवरी में दोनों देशों द्वारा युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत के साथ सीमित व्यापार उदारीकरण के प्रयास को प्रधान मंत्री इमरान खान ने आखिरी समय में खारिज कर दिया था । मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी – जो इस्लामाबाद में वर्तमान सरकार का समर्थन करते हैं – ने अतीत में, भारत के साथ सामान्य व्यापार संबंधों का समर्थन किया था, लेकिन सेना की सहमति नहीं मिल सकी (गांगुली 2015, पृष्ठ संख्या –1)।

जबकि वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने का आह्वान किया था, इमरान खान ने व्यापार उदारीकरण पर रोक लगा दी। उनका तर्क था कि पाकिस्तान भारत के साथ तब तक व्यापार नहीं कर सकता जब तक कि दिल्ली कश्मीर में 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों को उलट नहीं देता। अब इमरान सड़कों पर ''आयातित सरकार'' (अमेरिका से, जिसने पूर्व प्रधान मंत्री के अनुसार, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची थी) के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अगर सरकार भारत के साथ व्यापार के लिए रास्ता खोलती है तो वह सरकार को चपत लगा सकता है। सेना, जिसे लंबे समय से पाकिस्तान के राजनीतिक और नीतिगत विवादों में निर्णायक मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, वर्तमान संकट को

सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए, इस पर बंटी हुई लगती है (हॉल 2022, पृष्ठ संख्या–9)।

इससे शहबाज़ के पास रचनात्मक नीति निर्माण के लिए बहुत कम जगह बची है जो पाकिस्तान की कुछ मौजूदा आर्थिक समस्याओं को कम कर सकती है। इस बीच, युवा बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की कमान संभाली है, अपनी नौकरशाही की कश्मीर संबंधी घिसी–पिटी बातों से बंधे हुए हैं। दिल्ली के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के प्रति अपनी आत्म–पराजय नीति को बदल सकती है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या–1)। लेकिन उसे यह शर्त रखनी चाहिए कि भौगोलिक अनिवार्यता अंततः इस्लामाबाद की नीतियों पर हावी होगी।

दिल्ली में निराशावादी कहेंगे कि ''अंततः'' शब्द का आज नीति–निर्माण के लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन आशावादी कहेंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ काम करने के तरीके तलाशते रहना चाहिए। यथार्थवादी यह तर्क देना चाह सकते हैं कि उपमहाद्वीप में मौजूदा रुझान अपने पड़ोस को आकार देने में भारत की बढ़ती एजेंसी की ओर इशारा करते हैं और पाकिस्तान हमेशा अपवाद नहीं रहेगा। दिल्ली के लिए नीतिगत सवाल यह है कि क्या भारत पाकिस्तान में अपरिहार्य बदलाव को तेज करने के लिए कुछ कर सकता है।

मोदी सरकार की दक्षिण एशिया के लिए रणनीति

क्षेत्रीय वर्चस्व और स्थिरता को बनाए रखना और दक्षिण एशिया में अतिरिक्त–क्षेत्रीय अभिनेताओं को सैन्य पैर जमाने से रोकना लंबे समय से भारत की क्षेत्रीय नीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, भारत ने अपने छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करने की इच्छा प्रदर्शित की। इसका प्रमाण श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप (1987–1990) और नेपाल की आभासी आर्थिक नाकेबंदी (1989–1990) में देखा जाता है।

दक्षिण एशिया में जहां भारत को वास्तव में नरम और कठोर दोनों शक्तियों को फैलाने और लागू करने की आवश्यकता है, जिसे वह वास्तव में उपयोग कर सकता है और करना चाहिए, पाकिस्तान जिसे एक सहयोगी राष्ट्र बनना चाहिए था, एक असंभव विचार अब एक कठिन पड़ोसी बन गया है। अन्य मुद्दों के अलावा, यह कथित तौर पर मुख्य रूप से जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण है। इससे पहले भारत अपनी नजरों में सबसे अच्छा व्यापार भागीदार नहीं था, पाकिस्तान के शीर्ष 10 निर्यातकों में शामिल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के शीर्ष 10 देशों की सूची में था जहां से वह आयात करता था। एक दशक से अधिक समय से शत्रुतापूर्ण संबंधों के बाद, हाल के चरण में इसने अपने व्यापार संबंधों को भी खंडित कर दिया है (भारतीय वैश्विक संबंध परिषद 2023, पृष्ठ संख्या–)।

इसके विपरीत, भारत के पाकिस्तान की तुलना में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय देशों के साथ अधिक व्यापारिक संबंध थे, यह समझ में आता है। इसे बदलने की जरूरत है क्योंकि दोनों तरफ के मध्यम स्तर के व्यवसायियों को लाभ होगा। सांस्कृतिक रूप से पड़ोसी संबंधों में सुधार हो सकता है – कविता, संगीत, कला, रंगमंच आसानी से साझा किए जाते हैं और आनंद लिया जाता है। हालाँकि, पाकिस्तान ने 15 जुलाई 2020 से अफगानिस्तान को अटारी में वाघा सीमा (5 करोड़ रुपये से अधिक माल वाले 14 ट्रक) का उपयोग करके सामान भेजने की अनुमति देने में रियायत दी। शायद यह एक टेकऑफ़ बिंदु हो सकता है; व्यापार का उपयोग भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों के साथ–साथ सैन्य समस्याओं और रणनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए भी किया जा सकता है।

भारत को चीन, डगमगाते अमेरिका और लगभग स्थायी दुश्मन पाकिस्तान के अलावा अन्य चुनौतियों का भी सामना करना होगा। इसे अपने अन्य पड़ोसियों के साथ सक्षमतापूर्वक और सहजता से जुड़ना होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा सात देशों से लगती है। हाल ही में बांग्लादेश के साथ इसके संबंध अच्छे और संतुष्टिदायक रहे हैं। बांग्लादेश एक कपड़ा केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, यहां तक कि महामारी से लड़ने के लिए भारत के साथ एक टास्कफोर्स बनाकर भी उसने अपने कोविड–19 मामलों को प्रबंधनीय बनाए रखा है।

भारत–बांग्लादेश का व्यापार बढ़ा है। चटगांव से कंटेनरशिप उस समुद्री मार्ग को आसान बनाती है जिससे द्विपक्षीय कनेक्टिविटी और व्यावसायिक सेवाएं बढ़ती हैं। इन संबंधों को ''समय परीक्षित और ऐतिहासिक'' कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश ने कश्मीर पर भारत की नीति से यह कहकर दूरी बना ली है कि यह एक आंतरिक मामला है। भारत बांग्लादेश के साथ सहायता और व्यापार करना जारी रखेगा, जो एक रणनीतिक और मैत्रीपूर्ण कदम है (पटनायक 2023, पृष्ठ संख्या–11)।

भूटान एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, लोकतंत्र की राह पर चलने वाला एक स्वर्ग राज्य रहा है और भारत के साथ उसका रिश्ता बराबरी का है। खुद को अलग–थलग, फिर भी मिलनसार। जलविद्युत क्षेत्र भारत–भूटान द्विपक्षीय सहयोग का प्रमुख क्षेत्र है। भूटान जलविद्युत से इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि उसकी लगभग 80 प्रतिशत अधिशेष बिजली भारत को निर्यात की जाती है और उन्होंने पूर्वी भूटान में खोलोंगचू नदी पर 600 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना विकसित करने के लिए अपना पहला संयुक्त उद्यम बनाया, जिसे 2025 में पूरा किया जाएगा।

भारत के साथ श्रीलंका के संबंध मुद्दों के आधार पर प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण दोनों हैं। तमिल मुद्दा भारतीय तमिलों के दिल के करीब है और समय–समय पर उठता रहता है। श्रीलंका अभी भी ईस्टर बम धमाकों से उबरने की कोशिश कर रहा है। 21 अप्रैल 2019 को चर्चों और हाई–एंड होटलों में भयानक चौंकाने वाले बम विस्फोट हुए। लगभग 290 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। इन बम विस्फोटों से श्रीलंका में मुसलमानों की समस्या और बढ़ गई और श्रीलंका को अपनी ईसाई और मुस्लिम आबादी से समझौता करना पड़ा। श्रीलंका में ब्टप्क19 के आंकड़े 2839 पुष्ट मामले, 11 मौतें और 291 सक्रिय मामले थे। इसके बावजूद चुनाव हुए।

राजनीतिक मोर्चे पर, चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, तमिल समुदाय को लगता है कि उसे वह न्याय, अधिकार और जवाबदेही कभी नहीं मिलेगी जिसकी उसने मांग की है। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया है, लेकिन महामारी के कारण हर तरफ विभाजन बढ़ गया है, जिसने सभी अभियानों को धीमा कर दिया है। चुनाव के नतीजों में प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे की पार्टी (एसएलपीपी) को 145 सीटें मिलीं और अब 5 सीटों की जरूरत है, इसलिए वर्तमान संविधान में बड़े संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए एक गठबंधन बनाया गया है। यह अल्पसंख्यक आबादी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस स्थिति को संभालने के लिए भारत को और अधिक प्रयास करने होंगे।

एक पड़ोसी के रूप में मालदीव बुनियादी ताकतों के सत्ता में आने तक एक उदार राष्ट्र रहा है। कुछ समय के लिए इसने अपना लोकप्रिय पर्यटन स्थल खो दिया। यह धीरे–धीरे उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहा है। भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। दोनों ने घनिष्ठ सैन्य, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध विकसित किए हैं। मालदीव में वर्तमान में 300 ब्टप्क 19 मामले हैं। चूंकि पर्यटन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा बनाता है, इससे मालदीव और अन्य क्षेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

आईएनएस केसरी ने 580 टन आवश्यक खाद्य पदार्थों के साथ–साथ चिकित्सा आपूर्ति भी की है। भारत ने मछली प्रसंस्करण संयंत्रों में भी मदद करने की कोशिश की है। मालदीव के साथ भारत की मैत्रीपूर्ण भागीदारी जारी है लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मोईज्जु ने भारत विरोधी नीति को प्राथमिकता दिया है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या–1)।

भारत के लिए चुनौतियाँ सबसे प्रमुख हैं, चीनी पहेली को सुलझाना, संयुक्त राज्य अमेरिका को लुभाना और पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। लेकिन भारत के पटल पर ध्यान देने की मांग करने वाले और भी मुद्दे हैं। उनमें से कुछ इसकी अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, यात्रा, व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। इसे प्रारूप को मौलिक रूप से बदलना होगा, अधिक आत्मनिर्भर और अंतर्मुखी बनना होगा, गांधी और ईएफ शूमाकर के ‘‘छोटा ही सुंदर है’’ द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भरता मॉडल पर वापस लौटना होगा।

एक और प्राथमिकता सैन्यीकरण होगी, एक महंगा आयात भारतीय वायु सेना को फ्रांस से राफेल जेट लड़ाकू विमानों के साथ उन्नत किया गया है। क्या यह विकास की कीमत पर किया जाएगा? तर्क यह है कि बदलाव लाने के लिए, पर्याप्त होने के लिए एक बेड़े की आवश्यकता होती है। परमाणु हथियार और परमाणुकरण का क्या स्थान है, इस पर कोई बात नहीं हुई है। यह निश्चित रूप से वर्तमान महामारी के कारण है। इसे अंशांकित करने की आवश्यकता है।

आतंकवाद का भागफल कहीं नहीं जा रहा है। यह कई परतों के बीच छिपा हो सकता है, लेकिन यह ख़त्म होने वाली घटना नहीं है। इसे कम करने के लिए भारत ने इंटरपोल, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समझौते किए हैं। फिर भी कश्मीर में हालिया उग्रवाद और चल रही आतंकवादी गतिविधियां इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि भारतीय राज्य को आतंकवाद से न केवल सेना बल्कि टिकाऊ नीति के साथ निपटना होगा।

अंत में, किसी को यह कहना होगा कि हालांकि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में विफल रहा है, लेकिन दक्षिण एशिया के आम मुद्दों को संबोधित करने के लिए कुछ विकल्प की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। भारत के पास दक्षिण एशियाई देशों को एकजुट करने की ताकत और हैसियत है। 73 वर्ष के भारत को अपने नेतृत्व को लोकतंत्र, राजनीतिक अधिकार, न्याय को लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नरम और कठोर दोनों शक्तियों के साथ जुड़ाव निश्चित रूप से दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में इसकी स्थिति में इजाफा करेगा।

निष्कर्ष

भारत की विदेश नीति में, इसका पड़ोस महत्वपूर्ण है। यह भारत की परिधि की सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा हुआ है, जो पारिवारिक संबंधों और उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक समानताओं वाले विविध जातीय समूहों की मातृभूमि है, जो अक्सर सीमाओं को तोड़ते हैं। 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन से ऐसे संबंध टूट गए। उत्तर–औपनिवेशिक राज्यों की राष्ट्र निर्माण की बहुसंख्यकवादी अवधारणा ने साझा सामाजिक–सांस्कृतिक समानता का तिरस्कार किया और राष्ट्रीय पहचान की ‘विशिष्टता’ पर जोर दिया, जिसने विभाजन के कारण उत्पन्न दरार को और बढ़ा दिया। यह रवैया अविश्वास और संदेह की विशेषता वाली मानसिकता में बदल गया और इसने उस सहयोग को रोक दिया जो क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को अनुकूलित कर सकता था।

अपने पड़ोसियों के साथ सुरक्षा संबंधों पर भारत के अत्यधिक जोर ने उसे अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की घरेलू राजनीति और विदेश नीति के प्रति अतिरिक्त सतर्क बना दिया। पड़ोसियों ने महसूस किया कि इस तरह की सतर्कता उनकी संप्रभु विदेश नीति विकल्पों में बाधा डालती है और उन्हें अपनी आंतरिक राजनीति को आकार देने में बाध्य करती है। परिणामस्वरूप, पड़ोसी भारत से नाराज़ हो गए। हालाँकि, भारत की पड़ोस नीति में कई बदलाव आए हैं – यह धीरे–धीरे सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन के रूप में अपने पड़ोसियों के साथ विकास साझेदारी बनाने के लिए एक स्पष्ट सुरक्षा–केंद्रित दृष्टिकोण से दूर जा रहा है

संदर्भ सूची

1. वेग्नर, क्रिस्चन (2020), "दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा प्रदाता के रूप में भूमिका", सिंगापुर विश्वविद्यालय प्रेस, वॉल्यूम–1, संख्या–8, पृष्ठ संख्या–1–33
2. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2019), भारत प्रमुख क्षेत्रों में: दक्षिण एशिया, URL: https://www.orfonline.org/expert-speak/india-in-pivotal-geographies-south-asia-54281
3. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (2022), पड़ोस प्रथम नीति, URL: https://www.mea.gov.in/Images/CPV/LS9700.pdf
4. मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (2023), भारत की दक्षिण एशिया नीति, URL: https://www.idsa.in/southasia
5. रंजन, अमित (2019), "भारत की दक्षिण एशिया नीतिः परिवर्तन एवं निरंतरता", द राउंड टेबल जर्नल, वॉल्यूम–108, संख्या–3, पृष्ठ संख्या–259–274
6. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), भारत–पाकिस्तान संबंध URL: https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/indo-pak-relations-how-to-deal-with-pakistans-anti-india-security-strategy
7. पटनायक, स्मृति (2022), "भारत का पड़ोसी प्रथम नीति", द राउंड टेबल जर्नल, वॉल्यूम–111, संख्या–3, पृष्ठ संख्या
8. हॉल, इयान (2015), "भारतीय विदेश नीति में मोदी सिद्धांत", अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आस्ट्रेलिया जर्नल, वॉल्यूम–69, संख्या–3, पृष्ठ संख्या–247–252
9. गांगुली, सुमित (2017), "भारत की विदेश नीति में मोदी की भूमिका", वाशिंगटन त्रैमासिक, वॉल्यूम–40, संख्या–2, पृष्ठ संख्या–131–143
10. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), दक्षिण एशियाई प्रवाह के समय भारत का नेतृत्व, URL: https://www.orfonline.org/research/indias-leadership-at-a-time-of-south-asian-flux
11. भारतीय वैश्विक संबंध परिषद (2024), भारत और दक्षिण एशिया URL: https://www.gatewayhouse.in/india-and-south-asia-what-to-expect-in-2024/